

तिथि 29 जनवरी 2026

समय 18:10

मुख्य समाचार

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा - भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता आत्मविश्वास से पूर्ण, प्रतिस्पर्धी और उत्पादक भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
- केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया - 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर सात दशमलव चार प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया।
- चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर चुनाव में भाजपा को मिली एक-तरफा जीत - सौरभ जोशी चंडीगढ़ के महापौर बने।
- उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) विनियम 2026 को स्थगित रखने के आदेश दिए।
- मौसम विभाग ने पहली फरवरी को हरियाणा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता आत्मविश्वास से पूर्ण, प्रतिस्पर्धी और उत्पादक भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट सत्र के दूसरे दिन आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा -

इस क्वार्टर के प्रारंभ में ही भारत और यूरोपीय यूनियन का प्रीपेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्ज्वल हैं उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर एंबिशियस भारत है, यह फ्री ट्रेड फॉर एसपिरेशनल यूथ है, ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से एक नया बाजार खुल गया है और देश के निर्माताओं को इसका लाभ उठाना चाहिए।

जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाएं और अगर उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के जाते हैं तो हम यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के खरीदारों के दिल जीत लेते हैं। दशकों तक उसका प्रभाव रहता है। कंपनियों का ब्रांड देश के ब्रांड के साथ नए गौरव को प्रस्थापित कर देता है।

श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए अगले 25 वर्ष महत्वपूर्ण होंगे।

देश में वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर सात दशमलव चार प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2026-27 में वृद्धि दर छह दशमलव आठ से सात दशमलव दो प्रतिशत के बीच रह सकती है। यह अनुमान आज संसद में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पेश आर्थिक सर्वेक्षण में व्यक्त किया गया।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में वृद्धि की मजबूत गति को बनाए रखा है। पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर सात दशमलव चार प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें घरेलू मांग का महत्वपूर्ण योगदान है। निजी उपभोग और पूंजी निर्माण से वृद्धि को समर्थन मिल रहा है, जबकि आपूर्ति पक्ष में सेवाओं का योगदान प्रमुख बना हुआ है। विनिर्माण गतिविधि मजबूत हुई है और कृषि क्षेत्र ने स्थिरता प्रदान की है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित कुल महंगाई दर घटकर एक दशमलव सात प्रतिशत रह गई है, जिसका मुख्य कारण सब्जियों और दालों की कीमतों में सुधार रहा है। सर्वेक्षण के अनुसार, मुद्रास्फीति की स्थिति अनुकूल बने रहने का अनुमान है।

सदन की अगली कार्यवाही अब पहली फरवरी को होगी। इस दिन केन्द्रीय बजट 2026-27 पेश किया जाएगा।

आज चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज की। सौरभ जोशी ने चंडीगढ़ के महापौर पद का चुनाव जीत लिया, उन्हें 18 वोट मिले। वहीं आम आदमी पार्टी के योगेश ढींगरा को 11 और कांग्रेस के उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह गाबी को 7 वोट मिले। हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार शर्मा ने बताया है की पार्षदों ने हाथ उठाकर महापौर के चुनाव के लिए मतदान किया, जिसकी निगरानी पीठासीन अधिकारी रमनीक सिंह बेदी ने की। वरिष्ठ उप महापौर के पद पर भी भाजपा के उम्मीदवार जसमनप्रीत सिंह विजयी रहे। उन्हें 18 वोट मिले। जबकि आप पार्टी के उम्मीदवार मुनव्वर खान को 11 वोट मिले। उप महापौर का पद भी भाजपा की उम्मीदवार सुमन शर्मा ने जीत लिया। सुमन शर्मा को 18 वोट मिले और आप से जसविंदर कौर को 11 वोट मिले । कांग्रेस ने वरिष्ठ उप महापौर और उपमहापौर के चुनाव में भाग नहीं लिया।

उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) विनियम, 2026 को स्थगित रखने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि इस बीच 2012 यूजीसी विनियम काम करेंगे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की एक पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए विनियमों के बारे में कुछ आपत्तियां व्यक्त कीं। न्यायालय ने सुझाव दिया कि विनियमों को एक समिति द्वारा फिर से देखा जाना चाहिए जिसमें प्रख्यात न्यायविद शामिल हों। अदालत ने कहा कि विनियम प्रथम दृष्टया अस्पष्ट हैं और इसका दुरुपयोग संभव हैं। न्यायालय ने संघ और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नोटिस जारी कर 19 मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

23 जनवरी को अधिसूचित किए गए इस विनियमन को कई याचिकाकर्ताओं ने मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी।

हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने आज कुरुक्षेत्र कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री राजेश नागर ने कहा कि हर माह की तरह इस बार आयोजित हुई कष्ट निवारण समिति की बैठक में आई 17 में से 11 समस्याओं का मौके पर समाधान कर दिया गया है वहीं बाकी बची शिकायतों में जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों द्वारा गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं उन पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए एक इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है।

मौसम विभाग ने पहली फरवरी को हरियाणा में कई जगहों पर और 31 जनवरी और 3 फरवरी को कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि राज्य में 2 फरवरी को भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है और कल कहीं कहीं घना कोहरा पड़ सकता है। विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, उसके बाद न्यूनतम तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी।

भिवानी के कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विशेषज्ञ डा. देवीलाल ने कहा कि हाल ही में हुई बरसात गेहूं, सरसो के लिए बहुत फायदेमंद है। हालांकि जहां ओलावृष्टि हुई है, वहाँ सरसों व चने की फसल को थोड़ा नुकसान हुआ है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान के साथ सटे भिवानी जैसे जिले में यहाँ कुछ क्षेत्र बारानी है तथा कुछ सिंचित है, 4 से 5 मिलीमीटर बरसात होना अच्छा है। इससे जहां गेहूं में बढ़वार होगी, वहीं सरसों की फसल को फलियां बनने के समय में बारिश का पानी मिलने से उत्पादन बढ़ेगा।

हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हरदीप सिंह दून ने कहा कि राज्य पुलिस किसी भी प्रकार के अपराध से निबटने के लिए पूर्णतया: सक्षम है। इसको लेकर प्रदेश पुलिस नई तकनीकों व बेहतरीन प्रशिक्षण के साथ आगे बढ़ रही है।

वे आज भिवानी पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने दौरे को लेकर बताया कि भिवानी जिले के पुलिस अधिकारियों को किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने, पुलिस गश्त बढ़ाए जाने व पुलिसकर्मियों को आम जनता की बातों को बेहतरीन तरीके से समझने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल के निर्देश पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर पुलिस को चुस्त व दुरुस्त रखने के लिए इस प्रकार की बैठकें की जा रही है।
